Sardar Sarovar Dam

2690. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what is the target date for completion of the Sardar Sarovar Dam as per the Tribunal's Order;

(b) whether there is any delay in construction of the Dam; and

(c) whether it is a 'fact that the construction of the Sardar Sarovar Dam was delayed due to delay in land acquisition and rehabilitation by Madhya Pradesh and Maharashtra?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) As per Tribunal Award, the construction of Sardar Sarovar Dam was required to be completed by December, 1989.

(b) and (c) For want of environment and forest clearance, the works of main dam could not be started till April, 1967. However, as far as construction of dam is concerned there is no delay vis-a-vis approved programme.

Drinking water to Basin States

2691. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of WATER RE SOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a meeting was held on February 3 and 4, 1992 by the Chairman, Central Water Commission regarding allotment of drinking water to Basin States on ad-hoc basis;

(b) whether Rajasthan State's requirements of drinking water, for wild life, Ghana Sanctuary and irrigation in that State which comes to 3.505 MAF were also discussed at the above mentioned meeting; and

(c) if, so, what is the outcome thereof and what amount of drinking water on ad-hoe basis is likely to *be* allotted to Rajasthan during 1992-93 and by when a decision is likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b) In pursuance of the decisions taken in the Inter-State meeting of the Chief Ministers of Basin States on sharing of Yamuna Waters held on 10-1-92, separate meetings were taken with the representatives of the States by the Chairman, Central Water Commission and Secretary (Water Resources) with a view to assess the drinking water needs of the various States on a common norm basis for the projected population in the year 2001 AD within the drainage basin of river Yamuna. Meetings with the representatives of Government of Rajasthan were held on 3rd and 4th February, 1992. During those meetings Rajasthan made additional demands including the one for wildlife in Ghana Sanctuary over and above the one arrived at on the basis of the common norms.

(c) On the basis of these discussions and keeping in view the limited availability of surplus Yamuna waters, a draft agreement giving various alternatives for allocation of surplus Yamuna waters, on an ad hoc basis for drinking water requirements has been worked out and circulated to Basin States for consideration at the next Inter-State meeting of the Chief Ministers scheduled for 28th March, 1992. The allocation for Rajasthan's drinking water needs would depend upon the agreement amongst the Basin States

सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाना

2692. श्री रणजीत सिंह :
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जनवरी, 1992 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित "प्रोजेक्ट कोस्ट्स सोर, सब आप्टिमल

बेनिफिट्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शुरू की गयी सिंचाई परियोजनाओं की भारी संख्या पूरी नहीं हो पायी है ;

(ख) कुल कितनी सिंचाई परियोजनाएं बनायी गयी हैं और उनमें से कितनी परियोजनाओं को 1991 के अंत तक पूरा कर लिया गया है ; और

(ग) अपूर्ण परियोजनाओं पर दिसम्बर, 1991 के अंत तक कितनी राशि व्यय की गयी है और उन्हें पूरा करने के लिये कितनी और राशि की आवश्यकता होगी तथा कितना समय लगने की आशा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) सिंचाई परियोजनाओं का प्रतिपादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा प्रतिपादित की गयी परियोजनाओं की संख्या के बारे में सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है न ही राज्यों द्वारा प्रतिपादित की गयी सभी परियोजनाएं उनके द्वारा ही क्रियान्वित की जाती है । सातवीं योजना के अंत तक किए गए आकलन के अनुसार, वर्ष 1951 से 1990 की अवधि के दौरान 255 वृहद् और 1070 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गयी थीं । इनमें से, वर्ष 1990 के अंत तक 83 वृहद और 777 मध्यम परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं ।

(ग) सातवीं योजना के अन्त तक अपूर्ण वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर 20,020 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गयी है तथा इनको पूरा करने के लिए 36,210 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है । सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में लिया गया समय निधियों के आबंटन, राज्यों द्वारा प्रदान की गयी पारस्परिक प्राथमिकताओं जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करता है ।

भूमि पर कृषि

2693 **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 186 मिलियन हैक्टेयर कृषि-योग्य भूमि पर कृषि की जाती है, यदि हां, तो कितनी भूमि को सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा चुका है और इसे सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत कब से लाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में सिंचित भूमि का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो यह लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कौन-कौन सी नई तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा कर लेने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (कृषि वर्ष 1987–88 के लिए नवीनतम उपलब्ध भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार, 184.943 मिलियन हेक्टेयर कुल कृषि योग्य क्षेत्र में से सकल सिंचित क्षेत्र 56.216 मिलियन हक्टेयर है ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

मध्य प्रदेश में कैलों नदी-बांध का निर्माण

2694. **श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल** : क्या जल संसाधन मंत्री कृपा करेंगे कि : यह बता की

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में कैलों नदी-बांध का निर्माण करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई योजना स्वीकृति हेतुभेजी है; और